



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 57] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 59(अ).—जबकि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 की उप धारा (i) द्वारा यथापेक्षित औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 को अन्य नियमों के साथ और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया था और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 23 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

इसलिए, केन्द्रीय सरकार अब उक्त अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 में नियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:—

“56क वार्षिक विवरणी- प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट व्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र छ1 में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड प्रदान करेगा।

परंतु यह कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए “इलेक्ट्रॉनिक रूप” शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।”

[फा. सं. जेड-20025/25/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: औद्योगिक विवाद (केंद्रीय)नियम, 1957 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 770 तारीख 10 मार्च, 1957 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 417 (अ) दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 59(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, among other rules, were published as required by sub-section (1) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Industrial Disputes (Central) Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Industrial Dispute (Central) Rules, 1957, for rule 56A, the following rule shall be substituted, namely:—

‘56A. Annual return.—Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form G1 on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).’.

[F. No. Z-20025/25/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Industrial Dispute (Central) Rules, 1957 was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 770, dated the 10th March, 1957 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.417(E) dated the 25th May, 2015.